

# Daily Current Affairs

Date : 15 December, 2025



## अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज अडैप्टेशन'
2.	स्वर्णनगरी में न्यायिक महाकुंभ...
3.	राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम
4.	सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान
5.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल रेफरी
6.	राष्ट्रीय मखाना बोर्ड
7.	भारत की जनगणना - 2027
8.	भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौता
9.	अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष-IFAD
10.	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: बीमा योजना
11.	अमृत-AMRUT
12.	भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार
13.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. भारत का वन्य अग्नि प्रबंधन प्रस्ताव

--:1:--



## राजस्थान परिदृश्य



### 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज अडैप्टेशन'



#### चर्चा में क्यों?

- बदलते जलवायु परिदृश्य के बीच प्रदेश में पहली बार जयपुर में आने वाले 50 वर्षों तक जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों, बारिश के बदलते पैटर्न और तूफानों की आशंकाओं पर गहन रिसर्च करने हेतु बनने वाला यह 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज अडैप्टेशन' मूल रूप से राजस्थान के लिए एक दीर्घकालिक क्लाइमेट "थिंक टैंक + रिसर्च लैब" और "वॉर्निंग सिस्टम" की तरह काम करेगा।



#### मुख्य बिन्दु:

- **घोषणा** : राज्य सरकार द्वारा बजट 2025 26 में, जिस पर लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- यह सेंटर जगतपुरा, जयपुर में बनेगा और यह राजस्थान का ऐसा पहला क्लाइमेट चेंज अडैप्टेशन सेंटर होगा।

--2--

# Daily Current Affairs

Date : 15 December, 2025



- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को इसकी जिम्मेदारी दी गई है; डीपीआर तैयार हो चुकी है और छह अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है।
- IIT जोधपुर को नॉलेज पार्टनर चुना गया है। आईआईटी जोधपुर और प्रदूषण नियंत्रण मंडल दोनों संस्थानों के बीच जल्द ही एमओयू साइन होगा।

## सेंटर क्या करेगा?

- अगले 50 वर्षों तक के लिए राजस्थान, खासकर जयपुर क्षेत्र में तापमान में बदलाव, बारिश के पैटर्न, सूखा, बाढ़, तूफान जैसी चरम घटनाओं के बारे में वैज्ञानिक डेटा और मॉडलिंग तैयार करेगा।
- यह डेटा नगरीय विकास, कृषि, आपदा प्रबंधन, जल संसाधन, स्वास्थ्य आदि विभागों को दिया जाएगा ताकि वे अपनी योजनाओं और नीतियों को जलवायु के अनुरूप ढाल सकें।
- संभावित आपदाओं व दुष्प्रभावों से बचाव के लिए पहले से एडवाइजरी, रणनीति और कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिससे तैयारी "प्रतिसादात्मक" के बजाय "पूर्व सक्रिय" हो सके।
- आम नागरिकों के लिए भी मौसम और जलवायु रुझानों के आधार पर दैनिक जीवन, खेती, शहरी डिज़ाइन आदि के बारे में जनजागरण और मार्गदर्शन किया जाएगा।

## महत्त्व क्यों है?

- यह सेंटर राज्य स्तर पर स्थानीय स्तर के क्लाइमेट रिसर्च को संस्थागत रूप देगा, जिससे बेहतर क्लाइमेट अडैप्टेशन प्लान, जल, कृषि व शहरीकरण की दीर्घकालिक नीति, और "ग्रीन बजट" जैसी पहलों को वैज्ञानिक आधार मिल सकेगा।

--3--

## स्वर्णनगरी में न्यायिक महाकुंभ...

### चर्चा में क्यों?

- स्वर्णनगरी जैसलमेर में 13-14 दिसंबर 2025 को पश्चिमी क्षेत्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के लगभग 20 वरिष्ठ न्यायाधीश तथा राजस्थान सहित पश्चिमी भारत के 4 राज्यों (राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र) के 150+ हाईकोर्ट व ज़िला न्यायाधीश भाग ले रहे हैं।
- **थीम :** "Advancing Rule of Law through Technology: Challenges and Opportunities"



### मुख्य बिन्दु:

- लंबित मुकदमों में कमी, न्याय में तकनीक (ई कोर्ट, वर्चुअल हियरिंग), न्यायिक पारदर्शिता, सरल व आमजन की भाषा में न्यायालयी आदेश, तथा एकीकृत न्यायिक नीति पर विचार मंथन।
- पश्चिम भारत व न्यायपालिका के बीच समन्वय मज़बूत करना, आधुनिक व टेक्नोलॉजी आधारित न्याय व्यवस्था की दिशा में रोडमैप बनाना, और सीमांत ज़िले जैसलमेर को राष्ट्रीय न्यायिक विमर्श से जोड़ना।

## राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम

### चर्चा में क्यों?

- 14 दिसम्बर 2025 को CM भजनलाल शर्मा ने जलमहल (जयपुर) पर राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता व श्रमदान कार्यक्रम में हिस्सा लिया, झाड़ू लगाई, पौधारोपण किया और लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। स्वच्छता को समाज और सरकार की साझा जिम्मेदारी बताते हुए स्वच्छता कर्मियों को "स्वच्छता योद्धा" कहकर PPE किट वितरित कीं और रोड स्वीपिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाई।



### मुख्य बिन्दु:

- 'Implementation Plan for Single-Use Plastic Free Cities' पुस्तिका का विमोचन कर एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक के लिए एक्शन प्लान लागू करने की घोषणा की।
- राजस्थान में SBM Gramin के तहत 2.62 लाख से अधिक व्यक्तिगत और 4,000+ सामुदायिक शौचालय निर्मित; करीब 42-43 हजार गांव ODF Plus घोषित होने की प्रगति बताई।
- 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' जैसे अभियानों से जल स्रोतों व संस्थानों की सफाई और जल संरक्षण को बढ़ावा देने की बात कही।

--:5:--

## सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान

### चर्चा में क्यों?

- 11-25 दिसंबर तक राज्यभर में चलने वाले "सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान" की शुरुआत CM भजनलाल शर्मा ने जयपुर के जनपथ स्थित अमर जवान ज्योति पर राज्य स्तरीय समारोह में की। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा जन-जागरूकता रथों और लगभग 500 ऑटोरिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों के महत्त्व पर जागरूकता फैलाएँगे।

### मुख्य बिन्दु:

#### मुख्य गतिविधियाँ

- सड़क सुरक्षा पोस्टर का विमोचन, उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ, दिव्यांगों को हेलमेट वितरण, और व्यावसायिक वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाकर रात में दृश्यता बढ़ाने का संदेश दिया गया।
- सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर अस्पताल पहुँचाने वाले नागरिकों को Good Samaritan Award से सम्मानित किया गया।

## ✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p><b>अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल रेफरी</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>राजस्थान के लाल चंद ने उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एशियन वॉलीबॉल कंफेडरेशन द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल रेफरी परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल रेफरी का दर्जा प्राप्त किया। लाल चंद अब राजस्थान के तीसरे अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल रेफरी बन गए हैं।</li></ul>





## राष्ट्रीय परिदृश्य



### राष्ट्रीय मखाना बोर्ड



#### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मखाना क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना शुरू की गई। साथ ही अनुसंधान, गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन, मूल्य संवर्धन और निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक रोडमैप को भी मंजूरी दी गई।



#### मुख्य बिन्दु:

##### राष्ट्रीय मखाना बोर्ड:

- घोषणा:** केन्द्रीय बजट-2025-26
- मंत्रालय:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
- अवस्थिति:** पूर्णिया, बिहार।
- लक्ष्य:** मखाना क्षेत्रक का मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और वैश्विक स्थिति को बढ़ावा देना।

## भारत की जनगणना - 2027

### चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय मंत्रीमण्डल ने भारत की जनगणना-2027 को मंजूरी प्रदान की। यह देश की 16वीं तथा स्वतंत्रता के बाद आयोजित होने वाली 8वीं जनगणना होगी।



### मुख्य बिन्दु:

- **चरणबद्ध संचालन :-** यह प्रक्रिया दो चरणों में होगी:-
- अप्रैल से सितंबर 2026 तक मकान सूचीकरण और आवास गणना तथा फरवरी 2027 तक जनसंख्या प्रगणना।
- प्रथम डिजिटल जनगणना जिसमें मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा।
- जनसंख्या प्रगणना चरण के दौरान जातिगत डेटा को भी दर्ज किया जाएगा।

### भारत में जनगणना :-

- **उत्पत्ति :-** पहली गैर - समकालिक जनगणना 1872 में आयोजित की गई थी।
- **आयोजक :-** गृह मंत्रालय के तहत भारत का रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय।
- **वैधानिकता :-** जनगणना अधिनियम - 1948 जनगणना संचालन को कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- **पिछली जनगणना :-** विगत जनगणना 2011 में की गई थी। 2021 की जनगणना को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था।

## अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

### भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौता

#### चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय मंत्रीमण्डल ने भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है। ओमान की संसद के निचले सदन से मंजूरी मिल गई है।



#### मुख्य बिन्दु:

##### प्रमुख विशेषताएँ

- व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के साथ, भारत को ओमान में अपने 98 प्रतिशत उत्पादों तक पहुँच प्राप्त होगी और सेवाओं में भी महत्वपूर्ण पहुँच मिलेगी।
- व्यापार के अलावा, दोनों पक्षों के बीच निवेश प्रवाह को भी इस समझौते से लाभ होने की उम्मीद है।

##### मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

- FTA में दो व्यापारिक साझेदार अपने बीच व्यापार योग्य अधिकतम वस्तुओं पर सीमा शुल्क को या तो काफ़ी कम कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं।
- वे सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए नियमों में ढील भी देते हैं।
- भारत का खाड़ी सहयोग परिषद् (GCC) के एक अन्य सदस्य देश यूएई के साथ पहले से ही इसी तरह का समझौता है, जो 2022 में लागू हुआ था।

--:10:--

## अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष-IFAD

### चर्चा में क्यों?

- रोम में आयोजित IFAD इंडिया के कार्यक्रम में भारत ने ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और जलवायु लचीली कृषि के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया।



### मुख्य बिन्दु:

#### IFAD:-

- **स्थापना :-** 1977 ई., रोम, इटली।
- यह विकासशील देशों में लक्षित वित्तपोषण के माध्यम से ग्रामीण गरीबी से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है।
- यह मुख्य रूप से छोटे किसानों, पशुपालकों व ग्रामीण उद्यमियों को रियायती ऋण, अनुदान एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

## महत्त्वपूर्ण योजनाएँ

### प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: बीमा योजना

#### चर्चा में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय ने "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना" के तहत कोविड ड्यूटी में जान गंवाने वाले सभी चिकित्सकों को ₹50 लाख के बीमा के दायरे में लाने का निर्देश दिया।



#### मुख्य बिन्दु:

#### PMGKY पैकेज: स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना:

- उद्देश्य:** कोविड-19 ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
- मंत्रालय:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
- बीमा कवरेज:** प्रति लाभार्थी ₹ 50 लाख का बीमा कवर।
- लाभार्थी:** डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स और सहायक कर्मचारियों सहित COVID-19 ड्यूटी में प्रत्यक्ष रूप से शामिल स्वास्थ्य सेवा कर्मी।
- PMGKY पैकेज बीमा योजना मार्च, 2020 में शुरू किए गए व्यापक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक विशिष्ट घटक है।

--:12:--

## अमृत-AMRUT

### चर्चा में क्यों?

- लोकसभा में कार्याकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अमृत मिशन (AMRUT) पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।



### मुख्य बिन्दु:

#### अमृत मिशन :-

- शुरुआत - जून, 2015
- अमृत 2.0 - 1 अक्टूबर, 2021
- मंत्रालय - केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय।
- योजना का प्रकार - केन्द्र प्रायोजित योजना।
- उद्देश्य - चयनित शहरों और कस्बों में जलापूर्ति, सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित क्षेत्र एवं पार्क, गैर मोटर चालित शहरी परिवहन के लिए मूलभूत शहरी अवसंरचनाओं का विकास।

## आर्थिक परिदृश्य

### भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार

#### चर्चा में क्यों?

- नीति आयोग ने "भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को गहरा करना" शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की है।



#### मुख्य बिन्दु:

#### रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिन्दु:

- यह रिपोर्ट भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करने, चुनौतियों तथा भविष्य की कार्ययोजना का विश्लेषण करती है, जो निगमों, बुनियादी ढाँचे, लघु एवं मध्यम उद्यमों और उभरते क्षेत्रों के लिए वित्त पोषण का एक प्रमुख साधन है।
- एक मजबूत और तरल कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार दीर्घकालिक पूँजी जुटाने में मदद करता है, जिससे बैंड ऋण पर अत्यधिक निर्भरता कम होती है और आर्थिक विकास को समर्थन मिलता है।

# Daily Current Affairs

Date : 15 December, 2025



## कॉर्पोरेट बॉन्ड:

- कॉर्पोरेट बॉन्ड निजी तथा सार्वजनिक निगमों द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियाँ हैं।
- कंपनियाँ विभिन्न उद्देश्यों के लिए धन जुटाने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करती हैं, जैसे- नया संयन्त्र लगाना, उपकरण खरीदना, व्यवसाय का विस्तार करना।
- जब कोई व्यक्ति कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदता है, तो वह बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी, जिसे जारीकर्ता कहा जाता है, को पैसा उधार देता है।
- इसके बदले में कंपनी एक निश्चित परिपक्वता अवधि पर मूल धन लौटाने का वादा करती है। उक्त तिथि तक, कंपनी आमतौर पर एक निश्चित ब्याजदर का भुगतान करती है।

UTKARSH

CIVIL  
SERVICES

-:15:-

## ✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p><b>भारत का वन्य अग्नि प्रबंधन प्रस्ताव</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>भारत का "जंगल की आग के वैश्विक प्रबंधन को मजबूत करना" शीर्षक वाला प्रस्ताव केन्या के नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (DNA-7) के 7 वें सत्र में अपनाया गया।</li></ul>

